मेसर होल्डिंग्स लिमिटेड।

वी.

श्याम मदन मोहन रुइया और अन्य

(2010 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 33429-33434)

19 अप्रैल, 2016

[जे. चेलामेश्वर और अभय मनोहर सप्रे, जे. जे.]

कंपनी कानूनः शेयरों का हस्तांतरण- अपील के तत्काल सेटों में, शेयरों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन से संबंधित पक्षों द्वारा कई मुकदमे दायर किए गए थे-जबकि एक मुकदमा वापस ले लिया गया था, अन्य मुकदमे लंबित रहे- विभिन्न अंतर्वर्ती कार्यवाही से तत्काल एसएलपी उत्पन्न हुए-एसएलपी का निपटान, अदालत ने कहाः इन एस. एल. पी. में याचिकाआदेश्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों की जांच पूरी तरह से अनावश्यक है-इस मुकदमे पर काफी न्यायिक समय खर्च किया गया है-इस मुकदमे में किसी भी पक्ष का आचरण स्वस्थ नहीं है-लगभग 18 कार्य दिवसों की अवधि के लिए दोनों पक्षों की ओर से तर्क दिए गए थे जैसे कि यह न्यायालय मुकदमों की सुनवाई आदेश वाला मूल क्षेत्राधिकार का न्यायालय था तथ्य यह है कि अब तक किसी भी मुकदमे में मुद्दे भी नहीं बनाए गए हैं-यह मामला पैसे की शक्ति के साथ बेईमान मुकदमियों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, यह सब कानूनी अधिकारों के नाम पर आधा सच, भ्रामक अभ्यावेदन और पक्ष को दबाने का सहारा लेआदेश किया गया है-प्रत्येक पक्ष एक या दूसरे के लिए दोषी है।

रामरामेश्वरी देवी और अन्य बनाम निर्मला देवी और अन्य 2011 (8) एससीआर 992:(2011) 8 एस. सी. सी. 249-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

2011(8)एस.सी.आर.992 पर निर्भर पैरा 44

सिविल न्यायनिर्णयः विशेष अनुमति याचिका सं. 33429-33434 / 2010 ।

2005 के प्रस्ताव सं. 1308 के साथ 2001 के मुकदमा 509 में 2002 के प्रस्ताव सं. 534 में 2003 के अपील सं. 855 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से, 2005 का प्रस्ताव सं. 3965, 2007 का प्रस्ताव सं. 418, 2008 का प्रस्ताव सं. 1973, 2008 का प्रस्ताव सूचना सं. 1418।

ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. एल. श्रीगेश, श्रीमती वी. एस. लक्ष्मी, ए. वेनायगम बालन, सुश्री अरुणा गुप्ता, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

एफ. एस. नरीमन, रोहित कपाड़िया, एस. गणेश, वरिष्ठ अधिवक्ता।, कार्ल श्राफ, आर. एन. करंजावाला, देबमाल्या बनर्जी, जसमीत सिंह, ए. एस. अमन, मनीष शर्मा, सुश्री तान्या पुजजी, श्रीमती माणिक करंजावाला, सुभाष शर्मा (मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी के लिए), ई. सी. अग्रवाल, निखिल स्वामी, श्रीमती प्रभा स्वामी, सुश्री अरुणा गुप्ता, सुश्री मोहना एम. लाल, सुश्री गीताली तालुकदार, अधिवक्ता।प्रतिवादीओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय चेलामेश्वर, जे. द्वारा दिया गया था

1. मेसर ग्रीशम जीएमबीएच, एक जर्मन कंपनी (इसके बाद "एमजीजी" के रूप में संदर्भित) ने 12.5.1995 पर गोयल गैस लिमिटेड (इसके बाद "जीजीएल" के रूप में संदर्भित) नामक एक भारतीय कंपनी के शेयरधारकों के साथ एक शेयर खरीद और सहयोगसमझौता (इसके बाद एग्रीमेंट-1 के रूप में संदर्भित) किया। उक्त समझौते के आधार पर, एमजीजी ने जीजीएल के 30 प्रतिशत इक्विटी शेयर खरीदे। इसके बाद, एम.जी.जी. ने जी.जी.एल. में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी, एग्रीमेंट-1 के खंड 9 में लिखा हैः

"9, गैर-प्रतिस्पर्धा वर्ग

जी.जी.एल. और गोयल समूह की सभी कंपनियां भारतीय बाजार में पहले इनकार करने के अधिकार के आधार पर/एम.जी.जी. के साथ सहयोग करेंगी और इस सहयोग की अवधि के लिए गैस व्यवसाय के संबंध में एम.जी.जी. के प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से समर्थन नहीं देंगी। एमजीजी जीजीएल को औद्योगिक गैसों और संबंधित व्यवसाय के संबंध में भारतीय बाजार में हर व्यावसायिक अवसर के बारे में लिखित जानकारी देगा और जीजीएल यह तय कर सकता है कि वह इसमें भाग लेना चाहता है या नहीं (पहले इनकार करने का अधिकार)। यदि जी.जी.एल. एम.जी.जी. का नोटिस प्राप्त करने के बाद दो महीने की अवधि के भीतर लिखित रूप में यह घोषणा नहीं करता है कि वह नियोजित व्यवसाय में भाग लेने के लिए इच्छुक और समर्थ है, तो एम.जी.जी. अपने दम पर इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि, एम.जी.जी. अपनी समूह कंपनी होने के नाते जी.जी.एल. के हित पर विचार करेगी। एम.जी.जी. द्वारा शुरू किया गया ऐसा नया व्यवसाय केवल कुछ प्रमुख समर्पित ग्राहकों की गैस आपूर्ति का व्यवसाय होना चाहिए न कि सामान्य बाजार आपूर्ति का।"

2. बॉम्बे ऑक्सीजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद 'बी.ओ.सी.एल.' के रूप में संदर्भित) के रूप में जानी जाने वाली कंपनी में अधिकांश शेयर सामूहिक रूप से आर.यू आई.ए.एस. के रूप में जाने जाने वाले व्यक्तियों के एक समूह के पास थे (हम समझते हैं कि वे एक परिवार से संबंधित हैं)। 23.6.1997 पर, एमजीजी ने आरयूआईएएस के साथ एक और शेयर खरीदसमझौता (जिसे इसके बाद एग्रीमेंट-II के रूप में संदर्भित किया गया है) किया। उक्त समझौते से एम.जी.जी. ने (i) आर.यू आई.ए.एस. से बी.ओ.सी.एल. के 45001 शेयर खरीदने और (ii) खुले बाजार से बी.ओ.सी.एल. के और 30,000 शेयर हासिल करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे एम.जी.जी. बी.ओ.सी.एल.

का बहुसंख्यक शेयरधारक बन जाएगा (एक नियंत्रित ब्याज पैदा करना)।समझौता-II का खंड 6.1 पढ़ता है;

" 6.1 पहले इनकार करने का अधिकारः

यहसमझौता प्रभावी होने की तारीख से, कोई भी पक्ष पहले दूसरे पक्ष को शेयरों की पेशकश किए बिना कंपनी में अपने द्वारा आयोजित या अधिग्रहित किसी भी शेयर को नहीं बेचेगा। प्रस्ताव लिखित रूप में होगा और कीमत और अन्य नियमों और शर्तों में निर्धारित किया जाएगा। यदि प्रस्तावकर्ता इस प्रकार प्रस्तावित शेयरों को खरीदने के लिए सहमत नहीं होता है, तो प्रस्तावकर्ता किसी भी व्यक्ति (प्रस्तावकर्ता के प्रतिद्वंद्वी के अलावा) को शेयर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन उसी कीमत पर और उसी शर्तों पर जो प्रस्तावकर्ता को दी गई थी।पहले इनकार करने का यह अधिकार खरीदार द्वारा होक्स्ट समूह की किसी कंपनी को शेयरों की किसी भी बिक्री पर लागू नहीं होता है। होक्स्ट समूह के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य नियंत्रण द्वारा या उसके तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कंपनी में।इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए "नियंत्रण" का अर्थ है स्वामित्व, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या कंपनी के जारी और बकाया मतदान स्टॉक या स्वामित्व हित के 50 प्रतिशत से अधिक।"

3. समझौते-II के अनुसरण में, एम.जी.जी. ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 1997 (इसके बाद 'विनियमन 1997' के रूप में संदर्भित) के अध्याय-III के तहत जनता से बी.ओ.सी.एल. के 30,000 शेयरों का अधिग्रहण करने के अपने इरादे का खुलासा करते हुए एक सार्वजनिक घोषणा की, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (इसके बाद 'एस. ई. बी. आई. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की खंड 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई थी।

4. जी.जी.एल. ने बी.ओ.सी.एल. के शेयरों का स्वतंत्र रूप से अधिग्रहण करने के एम.जी.जी. के प्रयास का (लिखित रूप में) विरोध करते हुए कहा कि यह समझौता-I के खंड 9 का भंग होगा। इस संबंध में दोनों कंपनियों के बीच कुछ पत्राचार हुआ।अंततः दोनों कंपनियों ने 8.11.1997 पर समझौता-III किया, जिसके तहत इस बात पर सहमति बनी कि समझौता-II के तहत एमजीजी द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाले बीओसीएल के 75001 शेयरों में से 50,000 शेयरों का अधिग्रहण जीजीएल के नाम से किया जाएगा और केवल 25001 का अधिग्रहण एमजीजी के नाम से किया जाएगा।

5, आरयूआईएएस को एग्रीमेंट-एचआई के बारे में पता चला। आई. डी. 1 दिनांकित अपने पत्र द्वारा उन्होंने एम.जी.जी. को सूचित किया कि वे एम.जी.जी. और जी.जी.एल. के बी.ओ.सी.एल. के शेयरों को संयुक्त रूप से खरीदने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं थे। उक्त विकास को ध्यान में रखते हुए, एमजीजी ने जीजीएल को 7.5.1998 पर सूचित किया कि एमजीजी एग्रीमेंट-II को समाप्त कर रहा है। इसके बाद, एम.जी.जी. ने अपने दम पर बी.ओ.सी.एल. के 75001 शेयरों का अधिग्रहण किया और रु. 45001 शेयरों के मूल्य के लिए आर.यू आई.ए.एस. को 13.50 करोड़ रुपये।

<u>जी.जी.एल. आदि द्वारा दिल्ली के उच्च न्यायालय में सूट-1।</u>

6. 26.8.1998 पर, जी.जी.एल. ने एग्रीमेंट-I के खंड 9.1 को मुकदमा करने और अन्य राहतों के लिए एम.जी.जी. के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक दीवानी मुकदमा No.1810/98 (इसके बाद "एस. यू. आई. टी.-I" के रूप में संदर्भित) दायर कियाः

(क) बॉम्बे ऑक्सीजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और/या के 20 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के लिए प्रतिवादी द्वारा दिनांकित 6.8.1998 के प्रस्ताव पत्र को रद्द करें।

(ख) उस दिनांकित 23.6.1997 शेयर खरीद समझौते को रद्द करें जिसमें प्रतिवादी ने बॉम्बे ऑक्सीजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 30 प्रतिशत + 1 इक्विटी शेयर खरीदने की मांग की है और/या

(ग) बॉम्बे ऑक्सीजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 20 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के लिए दिनांकित 6.8.1998 प्रस्ताव पत्र और दिनांकित शेयर खरीद समझौते के अनुसरण में प्रतिवादी को कोई भी कदम उठाने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का एक डिक्री।23.6.1997 दिनांक 1 और/या के समझौते के गैर-प्रतिस्पर्धा खंड का उल्लंघन करते हुए बॉम्बे ऑक्सीजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 30 प्रतिशत + 1 इक्विटी शेयरों की खरीद के लिए।

(घ) प्रतिअभियोक्ता को बॉम्बे ऑक्सीजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अपने दम पर और अभियोक्ता की भागीदारी के बिना कोई भी शेयर प्राप्त करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश।

14.9.1998 पर, जी.जी.एल. ने कुछ अंतरिम आदेशों के लिए दो आवेदन दायर किए।आइए 1998 के एस. यू. आई. टी.-1 में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 1 और 2 (इसके बाद "सी.पी.सी". के रूप में संदर्भित) और 1998 के ओ. एम. पी. संख्या 205 में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "ए एंड सी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की खंड 9 का आह्वान किया गया है।दिलचस्प बात यह है कि दोनों आवेदनों में मांगी गई राहत काफी हद तक एक ही है, यानी एम.जी.जी. को बी.ओ.सी.एल. के शेयरों को अपने दम पर प्राप्त करने से रोकने वाला अंतरिम आदेश।विद्वत विचारण न्यायाधीश ने 22.9.1998 दिनांकित दो अलग-अलग आदेशों द्वारा दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया।जी.जी.एल. ने इस मामले को अदालत के भीतर की अपीलों में उठाया।

7. दिनांक 23.10.1998 के अपीलीय आदेश द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने रोक लगा दी!बी.ओ.सी.एल. के शेयरों के अधिग्रहण से एम.जी.जी.

8. उसी से व्यथित होकर, एम.जी.जी. ने 1999 की सिविल अपील संख्या 728 और 729 में इस न्यायालय का रुख किया। इस न्यायालय ने 18.12.1998 दिनांकित एक अंतरिम आदेश द्वारा निम्नानुसार आदेश दियाः-

> "इस बीच, याचिकाकर्ता मेसर्स ग्रीशेम जी. एम. बी. एच. के लिए जनता से 10,000 (एस. आई. सी. 30,000) शेयर खरीदने के लिए भुगतान करने और इन शेयरों की डिलीवरी लेने के लिए खुला रहेगा, लेकिन वे इन शेयरों के संबंध में शेयरधारकों के रूप में अपना नाम पंजीकृत कराने के उद्देश्य से आगे कदम नहीं उठाएंगे।
>
> प्रत्यर्थी संख्या 1 गोयल एम.जी. गैस लिमिटेड को आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपने मध्यस्थ को नामित करने और पूर्ण शुल्क का भुगतान करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया है और इसके बाद वह एक सप्ताह के भीतर अपने दावे का विवरण भी दाखिल करेगा।"

9. दिनांक 8.2.1999 के अंतिम आदेश द्वारा, उक्त अपीलों का निपटारा किया गयाः-

> "इससे पहले हमारे दिनांक 18.12.98 के आदेश द्वारा, हमने अपीलकर्ता को शेयरधारकों को भुगतान करने की अनुमति दी थी।भुगतान किए जाने के बाद अब उन शेयरों की अभिरक्षा अपीलकर्ता के पास है।बॉम्बे ऑक्सीजन एक बैंक से धन उधार लेना चाहता है और अपीलकर्ता उन शेयरों के बल पर एक उत्तरदायी बनना चाहता है और इस कारण से वह इस अदालत का एक आदेश चाहता है जो उसे ऐसा करने की अनुमति देता है।

हमें बताया गया है कि दो मध्यस्थ पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं और तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति कुछ ही समय में की जाएगी।प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हम निम्नलिखित आदेश पारित करना उचित समझते हैंः

मैसर ग्रीशेम जी. एम. बी. एच./अपीलकर्ता के लिए उन शेयरों को अलग करने और ऐसी वित्तीय व्यवस्था करने के उद्देश्य से उन्हें संबंधित बैंक की अभिरक्षा में रखने का अधिकार होगा।हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ तक शेयरों के पंजीकरण और स्वामित्व का सवाल है, वह मध्यस्थों द्वारा तय किया जाएगा।पक्षकारों के लिए यह खुला रहेगा कि वे उस ओर से अंतरिम राहत प्राप्त करने के लिए मध्यस्थों से संपर्क करें।

चूंकि शेयरों के पूर्व मालिकों को उनके बकाया का भुगतान कर दिया गया है, इसलिए वे उन शेयरों के मालिक नहीं रह गए हैं और उनमें लाभकारी ब्याज अब मेसर ग्रिशेम जीएमबीएच या मेसर ग्रिचेम जीएमबीएच और गोयल एचजी गैस लिमिटेड में संयुक्त रूप से निहित है यदि मध्यस्थ ऐसा तय करते हैं।हम निर्देश देते हैं कि बॉम्बे ऑक्सीजन के बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने के अधिकार सहित पक्षों के बीच सभी विवादों पर अब मध्यस्थों द्वारा निर्णय लेना होगा।यदि इस अदालत से संपर्क करने की कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो पक्षकारों के लिए ऐसा करना खुला रहेगा।जब तक मध्यस्थों द्वारा इसके विपरीत कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब तक हमारा 22.1.99 दिनांकित आदेश जारी रहेगा।

अपीलों का निपटान तदनुसार किया जाता है।"

10. 2010 के एसएलपी Nos.33429-33434 में याचिकाकर्ता (इसके बाद

'एमएचएल' के रूप में संदर्भित) एमजीजी द्वारा 20.01.2000 पर ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में निगमित एक कंपनी है और मॉर्गन ट्रेड एंड कॉमर्स के रूप में जानी जाने वाली एक अन्य कंपनी है जो जीजीएल की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एम.एच.एल. की अधिकृत शेयर पूंजी 10,000,000 डी.एम. (जर्मनी के संघीय गणराज्य की मुद्रा) है जो 10,000,000 शेयरों में विभाजित है।इसके दो निदेशक हैं, एक एमजीजी और दूसरा मॉर्गन ट्रेड एंड कॉमर्स का प्रतिनिधित्व करता है।एम.एच.एल. की दिलचस्प विशेषता यह है कि इस कंपनी के शेयर वाहक शेयर हैं।यह सभी पक्षों का एक स्वीकृत मामला है कि ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह का कानून इसकी अनुमति देता है।

11. एम.जी.जी. और जी.जी.एल. ने अपने विवाद (दिनांक 17.02.2000 और 13.3.2000 के दो दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित) का एकसमझौता किया, जिसके अनुसार एम.जी.जी. ने 1999 के सिविल अपील No.728-729 में दो आवेदन (2000 का आई. ए. 17 और 18) दायर किए, जिन्हें पहले ही 8.2.1999 पर निपटाया जा चुका था, यह प्रार्थना करते हुए किः

> "(क) उक्त 75001 शेयरों को मेसर होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम से हस्तांतरित और पंजीकृत करने की अनुमति दें और इन शेयरों से जुड़े पूर्ण अधिकारों को मेसर होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा प्राप्त करने की अनुमति दें, शेयरों के हस्तांतरण का पंजीकरण लंबित है और कानून के अनुसार बॉम्बे ऑक्सीजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए नामितों को अनुमति दें।
>
> (ख) निर्देश दें कि 23 अक्टूबर, 1998 से इस आवेदन में पारित आदेश की तारीख तक की अवधि को हस्तांतरण विलेखों की वैधता के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की खंड 108 (1 ए) के तहत निर्धारित अवधि की

गणना में बाहर रखा जाएगा।

(ग) ऐसा आगे का आदेश/आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।"

हालाँकि, जब कहा गया!.जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 20 तारीख को लिया गया था अप्रैल, 2000 में इस न्यायालय ने आदेश दियाः

"आवेदक और प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 के विद्वान वकील का कहना है कि जिस विवाद को मध्यस्थ को संदर्भित करने की मांग की गई थी, उसे उनके बीच सुलझा लिया गया है।इसे ध्यान में रखते हुए वे मध्यस्थता कार्यवाही से हटने के लिए उचित आवेदन करना चाहते हैं।वे इस उद्देश्य के लिए समय मांगते हैं।मामले को 5.5.2000 पर सूचीबद्ध करें।"

हम केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2000 के एल. ए. 17 और 18 में प्रार्थनाओं को दबाया नहीं गया था।

12. दिलचस्प बात यह है कि पहले शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही से पीछे हटने के लिए इस अदालत की अनुमति मांगने के बाद, एम.जी.जी. और जी.जी.एल. ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष 9.8.2000 पर एक संयुक्त आवेदन दायर किया जिसमें मध्यस्थ न्यायाधिकरण से सहमति पुरस्कार पारित करने का अनुरोध किया गया।इस तरह के आवेदन पर, आई. सी. सी. मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 21.9.2000 पर एक सहमति पुरस्कार पारित किया, जिसका परिचालन भाग इस प्रकार हैः

"अब इसलिए न्यायाधिकरण एतद्द्वारा संलग्नक "।" में निर्धारित संयुक्त आवेदन के संदर्भ में पक्षों की सहमति से निम्नलिखित निर्णय देता है, जो इस पुरस्कार का हिस्सा होगाः

(क) उत्तरदाता द्वारा बॉम्बे ऑक्सीजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.ओ.सी.एल.) के 75001 शेयर रुपये की कीमत पर खरीदे गए। मैसर होल्डिंग्स लिमिटेड (एम.एच.एल.) के नाम पर 22.5 करोड़ रुपये के शेयर रखे जाएंगे और पंजीकृत किए जाएंगे; हालाँकि, तकनीकी और प्रक्रियात्मक कारणों से शेयरों को पहले प्रतिवादी के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा और उसके तुरंत बाद उक्त शेयरों को एम.एच.एल. के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा जैसा कि उल्लेख किया गया है। संयुक्त आवेदन के पैरा 2 में।बी.ओ.सी.एल. के 75001 शेयरों से जुड़े पूर्ण अधिकारों के साथ-साथ उत्तरदाता को शेयरों के हस्तांतरण (हस्तांतरण-एस. आई. सी.) (यहां तक कि उत्तरदाता के नाम पर और/या एम.एच.एल. के नाम पर लंबित पंजीकरण) का प्रयोग अब से उत्तरदाता द्वारा एम.एच.एल. द्वारा से किया जाएगा जो उत्तरदाता के लिए और उसकी ओर से कार्य करेगा।एम.एच.एल. को मेसर ग्रीशेम जी. एम. बी. एच. (एम. सी. जी.) द्वारा बी.ओ.सी.एल. के शेयरधारकों की आम बैठकों में भाग लेने और उसमें मतदान करने और बी.ओ.सी.एल. के निदेशक मंडल में निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए नामितों को तय करने और नियुक्त करने के अधिकारों सहित ऊपर उल्लिखित अपनी सभी या किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

13. सहमति पुरस्कार के अनुसार, मई 2000 के महीने में किसी समय एम.जी.जी. ने बी.ओ.सी.एल. के 75001 शेयरों का शेयर प्रमाण पत्र एम.एच.एल. को विधिवत भरे गए हस्तांतरण फॉर्म और एक मुख्तारनामा के साथ सौंप दिया।

अन्य बातों के साथ साथ यह समझने के लिए दिया जाता है कि एस. यू. आई. टी.-I को अंततः जी.जी.एल. द्वारा वापस ले लिया जाता है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उस समय तक आर.यू आई.ए.एस. ने पहले ही (आई. डी. 1

पर) बॉम्बे उच्च न्यायालय अन्य बातों के साथ साथ एम.जी.जी. और जी.जी.एल. दोनों के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया था।

<u>सूट-2 आर.यू.आई.ए.एस. आदि. द्वारा बॉम्बे के उच्च न्यायालय में,</u>

14. 28.4.1999 में, आर.यू आई.ए.एस. ने समझौता-I के खंड 6.1 को मुकदमा करने की मांग करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय (इसके बाद एस. यू. आई. टी.-I के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक मुकदमा दायर किया।

"(क) I (i) कि यह घोषित किया जाए कि 23 जून 1997 के समझौते के खंड 6.1 में निहित नकारात्मक वाचा पूर्व है। यहाँ 'बी' प्रतिवादियों पर बाध्यकारी है;

(क) I (ii) (ख) कि प्रतिवादी स्वयं अपने अभिकर्ताओं और सेवकों को इस माननीय न्यायालय के स्थायी आदेश और निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित किया जाए।

(i) 23 जून, 1997 के समझौते के खंड 6.1 का भंग करना। यहाँ 'बी';

(ii) पूर्व में उल्लिखित सहित प्रतिवादी संख्या 2 के शेयरों में कानूनी और/या लाभकारी ब्याज को हस्तांतरित करना या बेचना या अलग करना। 23 जून 1997 के शेयर खरीद समझौते के खंड 6.1 के संदर्भ में वादी को पहले उसी की पेशकश किए बिना 'ए'। यहाँ 'बी' है।

iii) 23 जून 1997 के शेयर खरीद समझौते के खंड 6.1 का उल्लंघन करते हुए किसी भी मंच या अदालत से कोई पुरस्कार, डिक्री आदेश प्राप्त करना। यहाँ 'बी' है।

((iv) मध्यस्थों या किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई भी दावा करना जो यदि दिया जाता है तो 23 जून 1997 के उक्त शेयर खरीद समझौते के खंड

6.1 के प्रावधानों का भंग या भंग होगा। यहाँ 'बी';

(v) दिनांक 23 जून, 1997 के उक्त शेयर खरीद समझौते के खंड 6.1 के प्रावधानों के किसी भी भंग की प्राप्ति करना। 'बी' यहाँ; '

उक्त मुकदमे में, आर. यू. टी. ए. एस. ने एक आवेदन (1999 का प्रस्ताव का नोटिस No.1804) दायर किया जिसमें अनुरोध किया गया कि एम.जी.जी. और जी.जी.एल. को समझौता-II के खंड 6.1 का भंग करने से रोका जाए। दिनांक 6.5.1999 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, एम.जी.जी. और जी.जी.एल. को एग्रीमेंट-I के खंड 6.1 का भंग करने से रोक दिया गया था। एम.जी.जी. ने उक्त आवेदन में एक शपथ पत्र दायर किया कि यह समझौता-II के खंड 6.1 का भंग नहीं करेगा। 29, 2010 के एक आदेश द्वारा, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एमजीजी द्वारा दायर किए गए वचन को दर्ज करने वाले उक्त आवेदन का निपटारा एक और निर्देश के साथ किया कि एमजीजी और जीजीएल "बॉम्बे उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त किए बिना मध्यस्थों द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को मुकदमा या मुकदमा नहीं करेंगेः-

"पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों में निपटाने के लिए कोई कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

1. प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 23 जून 1997 के समझौते के खंड 6.1 के लिए तैयार है और उसका पालन करना करेगा।प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिए गए बयान को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया गया है।

प्रार्थना (ए) (आई) के संदर्भ में अंतरिम आदेश

2. प्रतिवादी संख्या। और 3 पहले अदालत की अनुमति प्राप्त किए बिना मध्यस्थों द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को लागू करने या लागू करने

के अनुसार कार्य नहीं करेंगे और अदालत वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच समझौते पर विचार करेगी।

3. उपरोक्त आदेश पक्षों के अधिकारों, दावों और तर्कों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया जाता है।

4, प्रस्ताव की सूचना का तदनुसार निपटारा किया जाता है।यह स्पष्ट किया जाता है कि पक्ष अपने-अपने अधिकारों को लागू करने के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

5. न्यायालय के सहयोगी द्वारा विधिवत प्रमाणित इस आदेश की प्रति पर पक्षकार (नोट-एस. आई. सी.) नहीं।"

15. 31 मई 2000 के एक पत्र द्वारा, आर.यू आई.ए.एस. ने एम.जी.जी. को सूचित किया और 1 जून 2000 को दोहराया कि समझौता-II को समाप्त कर दिया गया था।क्योंकि आर.यू आई.ए.एस. के अनुसार एम.एच.एल. की स्थापना और बी.ओ.सी.एल. के 75001 शेयरों का एम.एच.एल. को हस्तांतरण एग्रीमेंट-I1 के खंड 6.1 के भंग के समान है।

16. 21.9.2000 पर सहमति पुरस्कार प्राप्त करने के बाद, एमजीजी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एसयूआईटी-II में एक आवेदन (प्रस्ताव की सूचना No.2933/2000) दायर किया, जिसमें सहमति पुरस्कार को लागू करने और लागू करने के लिए अदालत की अनुमति मांगी गई।

<u>मुकदमा 3 बॉम्बे के उच्च न्यायालय में</u>

17, 5.2.2001 पर, आर.यू आई.ए.एस. ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 2001 (इसके बाद "एस. यू. आई. टी.-एच. आई. आई". के रूप में संदर्भित) का दूसरा मुकदमा दायर करते हुए अनुरोध किया:

"क) एक घोषणा के लिए कि 23 जून 1997 का शेयर खरीदसमझौता रद्द होने के लिए उत्तरदायी है;

ख) 23 जून 1997 के उक्त शेयर खरीद समझौते को रद्द करने के इस माननीय न्यायालय के आदेश के लिए;

ग)कि उपरोक्त प्रार्थना (क) और (ख) के विकल्प में, इस घोषणा के लिए कि 23 जून 1997 का शेयर खरीदअमान्य था और वादी द्वारा वैध रूप से टाल दिया गया है;

घ) कि उपरोक्त प्रार्थना (क), (ख) और (ग) के विकल्प में, इस घोषणा के लिए कि 23 जून 1997 का शेयर खरीद समझौता वादी द्वारा समाप्त किया जा सकता था और वादी द्वारा वैध रूप से समाप्त कर दिया गया है।

ई) कि उपरोक्त प्रार्थनाओं (ए), (बी), (सी) और (डी) के विकल्प में, इस माननीय न्यायालय द्वारा एक अनिवार्य आदेश और निर्देश के लिए प्रथम प्रतिवादी को 23 जून 1997 के शेयर खरीद समझौते के खंड 6.1 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वादी को उक्त 75,001 शेयरों की पेशकश करने का निर्देश दिया गया है।

च) एक घोषणा के लिए कि सार्वजनिक प्रस्ताव के अनुसार उक्त 30,000 शेयरों का अधिग्रहण अवैध, गैरकानूनी, अमान्य और शून्य है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है;

छ) इस घोषणा के लिए कि 17 फरवरी 2000 का उक्त समझौता और 21 सितंबर 2000 का उक्त सहमति पुरस्कार वादी और/या प्रतिवादी संख्या 2 पर बाध्यकारी नहीं हैं और/या वे अवैध, अमान्य हैं।

ज) प्रतिवादी संख्या 1,3 को रोकने वाला एक स्थायी निषेधाज्ञा

और 4 से

(क) 23 जून 1997 के शेयर खरीद समझौते के अनुसरण में कार्य करना;

(ख) उक्त 75,001 शेयरों के संबंध में किसी भी अधिकार का प्रयोग करना (विशेष रूप से इसके साथ आने वाले मतदान के अधिकार) और/या कोई लाभांश प्राप्त करने से, उसी के संबंध में अधिकार;

((ग) उक्त 75,001 शेयरों में, उन पर या उनके संबंध में अपने लाभकारी स्वामित्व सहित किसी भी अधिकार का प्रयोग करना।

क) कि प्रतिवादियों को इस माननीय न्यायालय के स्थायी आदेश और निषेधाज्ञा द्वारा वादी की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति, फर्म या निकाय के नाम पर उक्त 75,001 शेयरों को स्थानांतरित करने और/या पंजीकृत करने और/या पंजीकृत करने के लिए कोई कदम उठाने से रोका जाए।

ख) कि प्रथम प्रतिवादी को आदेश दिया जाए और 23 जून 1997 से सभी परिवर्धनों के साथ उक्त 45,001 शेयरों को संबंधित वादी को ऐसी शर्तों पर देने/वापस करने का आदेश दिया जाए जो यह माननीय न्यायालय निर्देश देता हैः

ट) उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रथम प्रतिवादी को आदेश दिया जाए और सभी कार्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने और निष्पादित करने और सभी दस्तावेजों, कार्यों और लेखन को आगे बढ़ाने के लिए आदेश दिया जाए।

18. उक्त मुकदमे में, आर.यू आई.ए.एस. ने एम.जी.जी. और जी.जी.एल. के साथ-साथ एम.एच.एल. के खिलाफ या तो एम.एच.एल. के मुकदमा में बी.ओ.सी.एल.

के 75001 शेयरों को हस्तांतरित करने या उक्त शेयरों के लाभकारी मालिकों के रूप में अधिकारों का प्रयोग करने के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक आवेदन (2001 का प्रस्ताव संख्या 392) दायर किया।उक्त मुकदमे में, एम.एच.एल. ने बी.ओ.सी.एल. की परिसंपत्तियों के प्रशासन के मुकदमा एक प्रशासक और रिसीवर की नियुक्ति के मुकदमा 21.2.2002 पर एक आवेदन (2002 का प्रस्ताव का नोटिस No.534) इस आधार पर दायर किया कि आर.यू आई.ए.एस. बी.ओ.सी.एल. की परिसंपत्तियों को पर्याप्त नुकसान पहुंचा रहा है।

19, एस. यू. आई. टी.-II को समय-समय पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 22.02.2000,04.10.2002 और 08.06.2011 के आदेशों के अनुसार तीन अवसरों पर संशोधित किया गया था।

ऐसे संशोधनों के बाद एस.यू.आई.टी.-II में प्रार्थना;

"राइडर-I (a)

(क) (i) इस घोषणा के लिए कि सार्वजनिक प्रस्ताव के अनुसार उक्त 30,000 शेयरों का अधिग्रहण अवैध, अमान्य और शून्य है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है।

(ii) प्रतिवादी को कथित 30,000 शेयरों के संबंध में किसी भी अधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए एक स्थायी आदेश और निषेधाज्ञा के लिए, जिसमें विशेष रूप से मतदान का अधिकार शामिल है।

(ख)(i) इस घोषणा के लिए कि 23 जून, 1997 का उक्त समझौता (प्रदर्शनी-ख) वैध रूप से समाप्त हो गया है और/या टाल दिया गया है।

राइडर-एन प्रार्थना (बी) (ii) (ए)

"(ख) (ii) (क) यह घोषित किया जाए कि प्रतिवादी संख्या 3 से 5

को प्रतिवादी संख्या 2 के 75001 शेयरों के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं है।

सवार-ओ प्रार्थना (बी) (इट) (बी):

"(ख) (ii) (ख) प्रार्थना के विकल्प में (ख) (ii) यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी को प्रतिवादी संख्या 2 के संबंधित वादी को 45001 शेयर देने और जनता के संबंधित सदस्यों को 35000 शेयर वापस करने का आदेश और निर्देश देता है।

(ii) कि चौथे प्रतिवादी संख्या 1,3,4 और 5 को आदेश दिया जाए और 23 जून, 1997 से संबंधित वादी को उक्त 45,004 75,001 शेयरों को सभी परिवर्धनों के साथ ऐसी शर्तों पर वितरित/वापस करने का आदेश दिया जाए जो इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित हैं।

(iii) उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रथम प्रतिवादी संख्या 1,3,4 और 5 को आदेश दिया जाए और सभी कार्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने और निष्पादित करने और सभी दस्तावेजों, कार्यों और लेखन को आगे बढ़ाने के लिए आदेश दिया जाए।

राइडर-पी प्रार्थना (बी) (iii) (ए)

"(ख) (iii) (क) कि प्रतिवादी संख्या 1 और 3 से 5 वादी को देने में विफल रहने की स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 के उक्त 75001 शेयरों को रद्द कर दिया जाए और प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश दिया जाए और वादी के नाम पर डुप्लिकेट शेयर जारी करने का निर्देश दिया जाए।

(iv) वादी की सहमति के बिना प्रथम और/या तीसरे और/या चौथे प्रतिवादी सहित किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति, फर्म या निकाय कॉर्पोरेट के नाम

पर उक्त 75,001 शेयरों को स्थानांतरित करने और/या पंजीकृत करने और/या पंजीकृत करने के लिए कोई कदम उठाने से प्रतिवादियों को रोकने वाले स्थायी आदेश और निषेधाज्ञा के लिए।

(v) प्रतिवादी एन. ओ. एस. को रोकने वाले स्थायी आदेश और निषेधाज्ञा के लिए। 1, 3 और/या 4 और 5 किसी भी अधिकार का प्रयोग करने से, जिसमें लाभकारी मालिक के रूप में, उक्त 75,001 शेयरों में, उन पर या उनके संबंध में शामिल हैं।

क(1) (i) वैकल्पिक और प्रार्थना की स्थिति में (ख) यह घोषित किया जाए कि 23 जून 1977 के समझौते के खंड 6.1 में निहित नकारात्मक वाचा पूर्व है। यहाँ 'बी' प्रतिवादियों पर बाध्यकारी है;

(क) (ii) कि प्रतिवादी स्वयं अपने अभिकर्ताओं और सेवकों को इस माननीय न्यायालय के स्थायी आदेश और निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित किया जाए।

(i) 23 जून, 1977 के समझौते के खंड 6.1 का भंग करना। यहाँ 'बी';

(ii) पूर्व में उल्लिखित सहित प्रतिवादी संख्या 2 के शेयरों में कानूनी और/या लाभकारी ब्याज को हस्तांतरित करना या बेचना या अलग करना। 23 जून 1997 के शेयर खरीद समझौते के खंड 6.1 के संदर्भ में वादी को पहले उसी की पेशकश किए बिना 'ए' यहाँ है। यहाँ 'बी' है।

(iii) 23 जून, 1997 के शेयर खरीद समझौते के खंड 6.1 का उल्लंघन करते हुए किसी भी मंच या अदालत से कोई पुरस्कार, डिक्री आदेश प्राप्त करना। यहाँ 'बी' है।

(iv) मध्यस्थों या किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई भी दावा करना

जो यदि दिया जाता है तो खंड 6.1 के प्रावधानों का भंग या भंग होगा।23 जून, 1997 के उक्त शेयर खरीद समझौते का पूर्व में उल्लेख किया गया है। यहाँ 'बी';

(v) दिनांक 23 जून, 1977 के उक्त शेयर खरीद समझौते के खंड 6.1 के प्रावधानों के किसी भी भंग की प्राप्ति करना। 'बी' यहाँ; '

राइडर-सी

(ख) (क) वैकल्पिक और प्रार्थना की स्थिति में (ख) मंजूर नहीं किया जा रहा है और यह अभिनिर्धारित किए जाने की स्थिति में कि उक्तसमझौता प्रतिवादी संख्या 1,4 और 5 अमान्य है, आदेश दिया जाए और संबंधित वादियों को उक्त 45001 शेयरों को 23 जून 1977 से सभी परिवर्धनों के साथ देने/वापस करने का आदेश दिया जाए।

(ख) उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रतिवादी संख्या 4 और 5 को अन्य कार्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने और निष्पादित करने और सभी दस्तावेजों, कार्यों और लेखन को आगे बढ़ाने के लिए आदेश और आदेश दिया जाए"

20. ऐसा प्रतीत होता है कि 5 दिसंबर को।2002, आर.यू आई.ए.एस. और एम.जी.जी. ने कथित रूप से समझौता-II को रद्द करके अपने बीच के विवादों कासमझौता (लिखित में एक समझौते द्वारा प्रमाणित) किया। एम.एच.एल. के अनुसार, समझौते की शर्तों के बारे में लंबे समय तक एम.एच.एल. या जी.जी.एल. को नहीं बताया गया था।5.12.2002 दिनांकित समझौते के बारे में जानकारी शुरू में संयुक्त राज्य अमेरिका के सुरक्षा विनिमय आयोग की वेबसाइट से MHL (कथित रूप से) के संज्ञान में आई थी।

समझौते का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः-

"6. इन परिस्थितियों में, "एमजीजी" और "रुइया" इस समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों पर "रुइया समझौते" को रद्द करके अपने सभी विवादों और मतभेदों को पूरी तरह से और अंत में निपटाने के लिए सहमत हुए हैं।हालांकि, "एमजीजी" "बीओसीएल" (जो "रुइया समझौते" का विषय है) के 45,001 शेयरों के लिए "रुइया" को शेयर प्रमाण पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज वापस करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वे "एमजीजी" के कब्जे में नहीं हैं।"एम.जी.जी. 45,001 शेयरों से संबंधित प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज साझा करता है और वापसी/वितरण को सुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है।

उसी से।

7. चूंकि "एम. जी. जी". अब "बी.ओ.सी.एल". में किसी भी शेयर के अधिग्रहण में रुचि नहीं रखता है, इसलिए समझौते के एक और हिस्से के रूप में, यह सहमति है कि "एम. जी. जी". इसके द्वारा "बी.ओ.सी.एल". में शेष 30,000 शेयरों में अपना पूरा अधिकार, शीर्षक और ब्याज "रुइया" के पक्ष में बेचता है/वापस करता है/स्थानांतरित करता है/विनिवेश करता है, जिसे "एम. जी. जी". ने जनता से प्राप्त किया था, लेकिन जिसे "बी.ओ.सी.एल". के रिकॉर्ड में "एम. जी. जी". के नाम से भी पंजीकृत नहीं किया गया है।हालांकि, "एमजीजी" को 30,000 शेयरों से संबंधित शेयर प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेजों के वर्तमान ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वह उसी की वापसी/वितरण को सुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है।

8. पूर्वगामी के विचार में, "रुइया" इस समझौते में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, "रुइया" को "एमजीजी" की ओर से किसी अन्य या आगे के दायित्व के बिना,

"बीओसीएल" के 75,001 शेयरों के संबंध में "एमजीजी" को 154,642 अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है।"रुइया" का इस समझौते में दिए गए प्रावधान के अलावा "एमजीजी" के लिए कोई और दायित्व नहीं होगा।

****** ***** ***** ******

10. पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि "एम. जी. जी". इसके द्वारा "रुइया" के पक्ष में उक्त 75001 शेयरों में या उनके संबंध में अपने सभी लाभकारी अधिकार, स्वामित्व और ब्याज को पूरी तरह से और अपरिवर्तनीय रूप से वापस/बेच, हस्तांतरण और निर्दिष्ट करेगा और "रुइया" की कीमत और व्यय पर ऐसे उपकरणों, दस्तावेजों, प्राधिकरणों आदि को निष्पादित और निष्पादित करना जारी रखेगा, जो इसके संबंध में आवश्यक या समीचीन ए हो सकता है और पूर्वगामी या इसके निष्पादन की तारीख से ऊपर के रूप में वापस किए गए/सौंपे गए/हस्तांतरित किए गए अधिकारों के साथ कुछ भी असंगत करने से परहेज करेगा।इस उद्देश्य के लिए, संलग्नक । के रूप में संलग्न मसौदे के अनुसार विधिवत निष्पादित एक अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी को सुश्री लीरा गोस्वामी, अधिवक्ता के साथ एस्क्रो में रखा जाएगा।सुश्री लीरा गोस्वामी "रुइया" और "एमजीजी" द्वारा सहमत लिखित एस्क्रो निर्देशों के अनुसार "रुइया" को पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपेंगी।

11(क) पक्ष इस बात की पुष्टि और स्वीकार करते हैं कि बी.ओ.सी.एल. के पूर्ववर्ती 45,001 शेयर बी.ओ.सी.एल. के अभिलेखों में "एम. जी. जी". के नाम से पंजीकृत नहीं हैं, इसलिए उक्त शेयर "रुइया" के नाम से पंजीकृत बने हुए हैं।नतीजतन, "रुइया समझौते" को रद्द करने में "बीओसीएल" की पुस्तकों में "एमजीजी" से "रुइया" में कोई स्थानांतरण शामिल नहीं है क्योंकि "रुइया" पंजीकृत शेयरधारक बने हुए हैं।फिर भी, यदि इस समझौते को लागू करने के लिए भारतीय कानून के तहत किसी भी

अनुमति, अनुमोदन या अधिसूचना की आवश्यकता है, जिसमें बिना किसी सीमा के, 154,642 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के लिए "भारतीय रिजर्व बैंक" की अनुमति शामिल है, तो "रुइया" ऐसे सभी आवश्यक अनुमोदन या अनुमति प्राप्त करने के लिए या "रुइया" की एकमात्र कीमत और खर्च पर आवश्यक फाइलिंग/अधिसूचना बनाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा।

(ख) इसी तरह, पार्टियां पुष्टि करती हैं और स्वीकार करती हैं कि "बीओसीएल" के पूर्ववर्ती 30,000 शेयर भी "एमजीजी" के नाम पर पंजीकृत नहीं किए गए हैं और भारतीय सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम पर बने हुए हैं।नतीजतन, "रुइया" वर्तमान में पंजीकृत शेयरधारकों से इन शेयरों के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी कार्यों, विलेखों और चीजों को करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

"रुइया" की एकमात्र कीमत और खर्च पर "रुइया" को।

****** ****** ****** *****

15. इस समझौते के निष्पादन पर, "रुइया" सहमत हैं:

(क) "एमजीजी" के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित निम्नलिखित कार्यवाहियों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा?" या इसके सहयोगी या इसके निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी ("एम. एच. एल". और "गोयल एम. जी. गैस लिमिटेड" को छोड़कर, लेकिन "एम. जी. जी". द्वारा "एम. एच. एल". और/या "गोयल एम. जी. गैस लिमिटेड" के बोर्ड में नामित निदेशकों सहित):

(i) 1999 का सिविल मुकदमा संख्या 2499 जिसका शीर्षक श्याम मदन मोहन रुइया और अन्य है। अन्य। मेसर ग्रीशेम जी.एम. बी.एच. और ओ.आर.एस.

(ii) श्याम मदन मोहन रुइया और अन्य शीर्षक वाला 2001 का दीवानी मुकदमा सं. 509। बनाम। मेसर ग्रीशेम जीएमबीएच एंड ओआरएस "।

उक्त समझौते के बावजूद, (जिसका अस्तित्व अब विवाद में नहीं है)। आरयूआईएएस ने न केवल एसयूआईटीएस 2 और 3 के साथ जारी रखा, बल्कि 08.06.2011 पर सूट-2 में भी संशोधन किया।

21. 4,2,2008 को बी.ओ.सी.एल. ने एच.डी.आई.एल. के नाम से जानी जाने वाली एक अन्य कंपनी के पक्ष में एक विकास समझौते को लागू किया, जिसमें आई. डी. 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में अचल संपत्तियों के तीन टुकड़ों के संबंध में विकास अधिकार दिए गए।एमटीआरएस।, 3513.70 स्क्वायर।एमटीआरएस।और 47762.20 वर्ग।एमटीआरएस।महाराष्ट्र के कुर्ला तालुक में स्थित भूमि कथित रूप से बी.ओ.सी.एल. के स्वामित्व में है।

22. अगले दिन बी.ओ.सी.एल. ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को उपर्युक्त विकास समझौते के बारे में सूचित किया।26.3.2008 पर, एच.डी.आई.एल. ने 230 करोड़ रुपये का सावधि ऋण प्राप्त करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में उपर्युक्त संपत्ति को गिरवी रखा।

23. 8.4.2008 एम.एच.एल. ने 2003° की अपील संख्या 855 में 2008 की प्रस्ताव संख्या 1418 की सूचना दायर की, जिसमें विभिन्न अन्य राहतों (जिनका विवरण वर्तमान के लिए आवश्यक नहीं है) के साथ उपर्युक्त विकास समझौते के पक्षों के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की गई।

24. 30 अप्रैल, 2008 के एक आदेश द्वारा, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने उक्त प्रस्ताव की सूचना की सुनवाई को स्थगित करते हुए एच.डी.आई.एल. की ओर से उपक्रमों को दर्ज किया कि वह उपरोक्त प्रस्ताव की सूचना में एम.एच.एल. की सफलता की स्थिति में किसी भी तरह की इक्विटी का दावा नहीं करेगी और एच.डी.आई.एल. द्वारा कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान किए गए निर्माण, यदि

कोई हो, को ध्वस्त कर देगी। उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि जो संपत्ति विकास समझौते का विषय थी, उसे पहले ही उनके पक्ष में गिरवी रखा जा चुका था। हालांकि, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उक्त संपत्ति में कोई तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं बनाने का बीड़ा उठाया।

25. उक्त आदेश से व्यथित होकर, एम.एच.एल. ने इस न्यायालय में 2008 की एस. एल. पी. संख्या 12734 8.5.2008 पर दायर की।दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने उक्त एसएलपी पर नोटिस जारी करते हुए विवादग्रस्त संपत्ति की प्रकृति, स्वामित्व आदि के संबंध में यथास्थिति का आदेश दिया।दिनांक 23.6.2008 के एक आदेश द्वारा, उक्त SLP को यह निर्देश देने से निपटा दिया गया था कि 16.5.2008 पर पहले दिया गया यथास्थिति आदेश बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तावों और अपीलों की सूचना विचाराधीनता रहने के दौरान जारी रहेगा।

एसयूटी-IV।

26. 23.4.2008 पर, MHL ने 2008 का मुकदमा No.2410 दायर किया (इसके बाद) विभिन्न राहतों की मांग करने वाले बी.ओ.सी.एल., आर.यू आई.ए.एस., एच.डी.आई.एल. आदि के खिलाफ मामला-IV) बी.ओ.सी.एल. ई. टी. ई. के 75001 शेयरों के स्वामित्व की घोषणा सहित।

"क) कि इस माननीय न्यायालय को यह घोषणा करते हुए खुशी हो कि अभियोक्ता प्रथम प्रतिअभियोक्ता कंपनी में 75001 शेयरों के सूट शेयरों का लाभकारी मालिक है, जिसे विशेष रूप से प्रदर्शनी ए के रूप में संलग्न अनुसूची में वर्णित किया गया है और वह इसके कानूनी स्वामित्व का हकदार है;

आर) कि प्रतिमुकदमी को इस माननीय न्यायालय के एक अनिवार्य आदेश और निषेधाज्ञा द्वारा सभी कार्यों, कार्यों और चीजों को पूरा करने और प्रथम

प्रतिमुकदमी कंपनी में कुल 75001 शेयरों के सूट शेयरों के पंजीकरण को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक सभी सहयोग देने का निर्देश दिया जाए, जो विशेष रूप से मुकदमी के नाम पर प्रदर्शनी ए में वर्णित है;

एस) कि इस माननीय न्यायालय को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मुकदमे के शेयरों का कथित प्रत्यावर्तन/हस्तांतरण प्रथम प्रतिमुकदमी कंपनी में 75001 शेयर है, जिसे विशेष रूप से प्रतिमुकदमी No.10 द्वारा प्रतिमुकदमी संख्या को प्रदर्शनी ए के रूप में संलग्न अनुसूची में वर्णित किया गया है।2 दिनांकित दिसंबर, 2002 के कथित समझौते के तहत 9 तक अवैध, अमान्य और कोई कानूनी प्रभाव नहीं है;

टी) कि यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी को 9 और 10 को उस समझौते को प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है जो पूर्व में 05.12.2002 दिनांकित हैःरद्द करने के लिए सी. सी. और यह माननीय न्यायालय इसे रद्द करने के लिए प्रसन्न होगा;

यू) कि यह माननीय न्यायालय 75001 मुकदमा शेयरों (विशेष रूप से संलग्न अनुसूची में प्रदर्शनी ए के रूप में वर्णित) के संबंध में किसी भी अधिकार का प्रयोग करने से प्रतिमुकदमी Nos.2 को रोकने के लिए एक आदेश और एक निषेधाज्ञा जारी करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर जनता का प्रतिनिधित्व करने से भी प्रसन्न होगा कि वे मुकदमा शेयरों के मालिक हैं और उनमें कोई लाभकारी हित है;

भी) कि इस माननीय न्यायालय को यह घोषणा करते हुए खुशी हो कि दिनांकित (आई. डी. 1) का कथित विकाससमझौता और दिनांकित (आई. डी. 2) की दोनों शक्तियां (एन. एन. और ओ. ओ. प्रदर्शित करें) और इसके अनुसरण में कोई अन्य दस्तावेज या कार्य अवैध, अमान्य और कोई कानूनी प्रभाव नहीं हैं।

डब्ल्यू) कि यह माननीय न्यायालय प्रतिवादियों को 10 और 12 को निर्देश देता

है कि वे दिनांकित विकास समझौते (आई. डी. 1) (एम. एम. को यहाँ प्रदर्शित करें) के साथ-साथ दिनांकित (आई. डी. 3) (एन. एन. और ओ. ओ. को यहाँ प्रदर्शित करें) को अवैध, अमान्य और रद्द करने के लिए कोई कानूनी प्रभाव नहीं है और यह माननीय न्यायालय इसे रद्द करने के लिए प्रसन्न है।

एक्स) कि इस माननीय न्यायालय को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि प्रदर्शनी XX में दिनांकित कथित बंधक विलेख जिसे प्रतिवादी No.12 द्वारा प्रतिवादी No.13 के पक्ष में बनाया गया था, अवैध, अमान्य और कोई कानूनी प्रभाव नहीं है;

बाई) यह कि यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी को 10,12 और 13 को निर्देश देता है कि वह दिनांकित बंधक के उक्त विलेख को यहां XX को प्रदर्शित करने या रद्द करने पर वितरित करे और यह माननीय न्यायालय इसे रद्द करने के लिए प्रसन्न हो;

जेड) कि यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या को आदेश और डिक्री देने के लिए प्रसन्न हो।2 10 से संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से अभियोक्ता को हर्जाना/मुआवजे का भुगतान करना, दावे के विवरण के अनुसार Rs.500 करोड़ की राशि के साथ मुकदमे की तारीख से भुगतान और/या प्राप्ति तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ ZZ को प्रदर्शित करें;

हम समझते हैं कि किसी भी प्रतिवादी ने अपना लिखित बयान दायर नहीं किया है और अभी तक कोई मुद्दा तैयार नहीं किया गया है।-

27. 1टी उपरोक्त मुकदमे की पृष्ठभूमि में है इन ए एसएलपी की जांच की जानी है।

2010 की एस.एल.पी.(सी) संख्या 33429-33434 एम.एच.एल. द्वारा प्रार्थना के साथ दाखिल की गई हैः

"क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विमुकदमाति अंतिम

न्यायाधीशों के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दें और बॉम्बे में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2003 की अपील संख्या 855 में 2001 के मुकदमा संख्या 509 में 2002 के प्रस्ताव संख्या 534 में 2005 के प्रस्ताव संख्या 1308,2005 के प्रस्ताव संख्या 3956,2005 के प्रस्ताव संख्या 3956 के नोटिस के साथ पारित आदेश।4118 2007 की सूचना, 2008 की सूचना सं. 1973, सी. सी. की सूचना सं. 1418 2008; और

क) ऐसा अन्य आदेश या आदेश पारित करें जिसे यह माननीय न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित समझे मामला।"

2012 का एस. एल. पी. (सी) Nos.23088-23090 जी.जी.एल. द्वारा प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया हैः

"क) 2003 की अपील संख्या 840,2003 की 841 और 2003 की 857 में बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.09.2010 के विमुकदमाति आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करें, जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया और Ld द्वारा पारित दिनांक 26.03.2003 के आदेश को बरकरार रखा। प्रस्ताव की सूचना संख्या 2000 की 3230,1999 की मुकदमा संख्या 2499 में 2003 की 1231 और 2001 की मुकदमा संख्या 509 में 2001 की 392 में एकल न्यायाधीश;

और

ख) ऐसे अन्य और आगे के आदेश पारित करें जिन्हें यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित समझे।"

एस. एल. पी. के दोनों सेट सिविल अपील संख्या 855/2003, 840/2003, 841/2003 और 857/2003 में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के दिनांक

01.09.2010 के सामान्य आदेश से व्यथित हैं।

28. सिविल अपील 855/2003 MHL द्वारा दायर की गई थी और अन्य तीन अपील GGL द्वारा दायर की गई थीं। प्रस्तावों की विभिन्न सूचनाओं के साथ सभी चार अपीलों को लागत के साथ खारिज कर दिया गया था।

29. अपील की विषय वस्तु No.855/203 एस. यू. आई. टी.-III में प्रस्ताव की सूचना 534/2002 में एकल न्यायाधीश का आदेश है। उक्त अपील में पांच प्रस्तावों की सूचना दायर की गई थी।वे हैं 1308/2005, 3956/2005, 4118/2007, 1973/2008 और 1418/2008 जो विभिन्न राहतों की मांग कर रहे हैं।

30. अपील का विषय सं।840, 841 और 2003 का 857 एस. यू. आई. टी.-II में एकल न्यायाधीश के प्रस्ताव की सूचना Nos.3230 2000 और 1231/2003 और मुकदमा III में प्रस्ताव की सूचना No.392/2001 का दिनांकित आदेश है। उपरोक्त दोनों मुकदमे आर.यू आई.ए.एस. द्वारा दायर किए गए थे।

31. इसलिए, एस. यू. आई. टी.-I को स्वीकार किया जाता है।उक्त मुकदमा विचाराधीनता रहने के दौरान किसी भी न्यायालय (इस न्यायालय सहित) द्वारा उक्त मुकदमा से उत्पन्न होने वाली किसी भी कार्यवाही में पारित कोई भी आदेश स्वतः ही मुकदमा को वापस लेने के साथ समाप्त हो जाता है।आदेशों के इस तरह के व्यपगत होने का एक तार्किक परिणाम यह है कि उक्त मुकदमा के किसी भी पक्ष का कोई भी कार्य या चूक, या तो ऐसे अंतर्वर्ती आदेशों के अनुसरण में या उनके पालन में, किसी भी कानूनी प्रभावकारिता के बिना होगा।

32. सूट आई!आर.यू आई.ए.एस. द्वारा दाखिल किए गए और तीसरे मामले आज तक लंबित हैं। एस.यू.आई.टी.- II का सार यह है कि आर.आई.ए.एस. नहीं चाहता कि एम.जी.जी. बी.ओ.सी.एल. के किसी भी शेयर को जी.जी.एल. या एम.एच.एल. या

किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में एम.जी.जी. द्वारा एग्रीमेंट-II के अनुसार अधिग्रहित किया जाए, बिना उन्हें आर.यू आई.ए.एस. को दिए। आर.यू आई.ए.एस. की राय में ऐसा स्थानांतरण समझौता-II के खंड 6.1 का उल्लंघन होगा।

एस.यू.आई.टी.-3 पर आते हुए, आर.आई.ए.एस. एग्रीमेंट-II से बाहर निकलना चाहता है और इसलिए, एग्रीमेंट-आई. पी. के तहत एम.जी.जी. द्वारा 75001 शेयरों के अधिग्रहण को रद्द करने की मांग करने वाली पदार्थ में वे इसके बाद की घटनाओं पर भी भरोसा करते हैं 23.06.1997 जीजीएल और एमजीजी आदि के बीच लेनदेन और विभिन्न की तलाश प्रार्थनाएँ जो पहले से ही देखी जा चुकी हैं। [एस.यू.आई.टी. -II] दाखिल करने के बाद, आर.यू.आई.ए.एस. ने एक बार फिर एस. यू. आई. टी.-II में संशोधन किया और मुकदमा का दायरा बढ़ाया।इस तरह के संशोधन कानूनी रूप से मान्य हैं या नहीं, यह एक ऐसा सवाल है जिसकी जांच कार्रवाई के कारणों आदि के जुड़ाव के सवाल पर कानून को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। इसके अलावा एस. यू. आई. टी.-आई. टी. और एस. यू. आई. टी.-III की निरंतरता एक साथ उनकी रखरखाव क्षमता के बारे में बहुत सारे सवाल उठाती है। हालाँकि, हमारे विचार में, ऐसे प्रश्नों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आर.यू आई.ए.एस. और एम.जी.जी. ने 05.12.2002 दिनांकित एकसमझौता किया है जिसका सार पैरा 20 (उपरोक्त) में पहले देखा गया है।उक्त समझौते के अनुसार, आर.यू आई.ए.एस. ने एस. यू. आई. टी. एस.-II और एच. आई. पर मुकदमा नहीं चलाने पर भी सहमति व्यक्त की, जहां तक मुकदमे "एम.जी.जी. या उसके सहयोगियों" आदि से संबंधित हैं।

> "(क) "एमजीजी" के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित निम्नलिखित कार्यवाहियों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा?" या इसके सहयोगी या इसके निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी

("एम. एच. एल". और "गोयल एम. जी. गैस लिमिटेड" को छोड़कर, लेकिन "एम. जी. जी". द्वारा "एम. एच. एल". और/या "गोयल एम. जी. गैस लिमिटेड" के बोर्ड में नामित निदेशकों सहित);

(i) 1999 का सिविल मुकदमा No.2499 जिसका शीर्षक श्याम मदन मोहन रुइया अन्य अन्य है।मेसर ग्रीशेम जी. एम. बी. एच. अन्य ओ. आर. एस.

(ii) 2001 का सिविल मुकदमा No.509 जिसका शीर्षक श्याम मदन मोहन रुइया अन्य अन्य है।मेसर ग्रीशेम जीएमबीएच एंड ओआरएस "।

वास्तव में, इन एसएलपी की सुनवाई के दौरान भी, आरयूआईएएस और एमजीजी दोनों ने एमएचएल और जीजीएल द्वारा दायर इन एसएलपी का विरोध करने में एक-दूसरे के मामले का समर्थन किया।

33. आरयूआईएएस द्वारा एमजीजी द्वारा से बीओसीएल के 75001 शेयरों में स्वामित्व का दावा करने के परिणामस्वरूप, हमने पहले ही देखा है कि उक्त 75001 शेयरों को एमजीजी द्वारा शुरू में आरयूआईएएस और जनता से एग्रीमेंट-II के तहत अधिग्रहित किया गया था। लेकिन, अब तक आर.यू आई.ए.एस. के नाम पहले उल्लिखित विभिन्न अंतरिम आदेशों के कारण शेयर धारकों के रूप में बी.ओ.सी.एल. के रजिस्टरों में दर्ज नहीं किए गए हैं।

34. हालाँकि, जी.जी.एल. और एम.एच.एल. ने उक्त 75001 शेयरों के लिए एम.जी.जी. के स्वामित्व पर विवाद किया।जी.जी.एल. और एम.एच.एल. के अनुसार, दिनांक 1 के समझौते से एम.जी.जी. ने उक्त शेयरों पर अपना अधिकार खो दिया था क्योंकि उसने पहले ही उक्त शेयरों में अपना अधिकार एम.एच.एल. के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया था।

35. उक्त 75001 शेयरों में एम.जी.जी. में स्वामित्व के अस्तित्व पर कम से कम सहमति पुरस्कार की तारीख तक जी.जी.एल. या एम.एच.एल. द्वारा विवाद नहीं किया जा सकता है, अर्थात <आई. डी. 1] क्योंकि उक्त शेयरों पर स्वामित्व के लिए जी.जी.एल. और एम.एच.एल. का दावा एम.जी.जी. के पूर्व स्वामित्व और सहमति पुरस्कार के अनुसार बाद के कथित हस्तांतरण से प्रवाहित होता है।ऐसे मामले में, एम.जी.जी. द्वारा 75001 शेयरों में स्वामित्व को आर.यू आई.ए.एस. को दिनांकित 53.12.2002 के तहत हस्तांतरित करने के कारण, आर. यू. टी. ए. एस. को आम तौर पर उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उक्त शेयरों के धारकों के रूप में बी.ओ.सी.एल. के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार होना चाहिए।यदि जी.जी.एल. या एम.एच.एल. में से कोई भी आर.यू आई.ए.एस. के पक्ष में उक्त हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के एम.जी.जी. के अधिकार पर आपत्ति जता रहा है, तो उन्हें उक्त शेयरों में एक बेहतर शीर्षक (एम.जी.जी. को) स्थापित करना होगा।यह बिना कहे चला जाता है कि यह केवल जीजीएल या एमएचएल या दोनों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई कुछ कानूनी कार्रवाई में ही किया जा सकता है।लेकिन वे आर.यू आई.ए.एस. द्वारा दायर एस. यू. आई. टी. एस.-II और III में अपने अधिकार की घोषणा की मांग नहीं कर सकते हैं। अपने शीर्षक को स्थापित करने के लिए एम.एच.एल. ने एस. यू. आई. टी.-IV दायर किया।एम.एच.एल. का अधिकार, यदि कोई हो, उक्त मुकदमा में तय करना होगा।जब तक उक्त मुकदमा का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक हम कानून में ऐसा कोई आधार नहीं देखते हैं जिस पर जी.जी.एल. या एम.एच.एल. दिनांकित समझौते 5.12.2002 के अनुसार आर.यू आई.ए.एस. के पक्ष में शेयरों के हस्तांतरण पर आपत्ति कर सकें।

36. आर.यू आई.ए.एस. को पता लगाना है कि दिनांकित 5.12.2002 के अनुसार शेयरों के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए आर.यू आई.ए.एस. को किस प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।क्योंकि तत्काल मुकदमेबाजी के लंबे समय तक

विचाराधीनता रहने के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन और डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 आदि के आगमन के आधार पर कंपनियों में शेयरों के हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के संबंध में कानून में काफी बदलाव हुआ है। हम यह अवलोकन इसलिए करते हैं क्योंकि एग्रीमेंट-II के अनुसार एम.जी.जी. द्वारा अधिग्रहित 75001 शेयरों को एम.जी.जी. के नाम से पंजीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि विभिन्न न्यायालयों द्वारा मुकदमा आई. टी. एस.-1, आई और एच. आई., मुकदमा आई. टी.-1 में विभिन्न चरणों में पारित विभिन्न अंतरिम आदेशों को अभियोक्ता (जी.जी.एल.) द्वारा वापस ले लिया गया था।एम.जी.जी. और आर. यू. आई. ए. ए. एस. के बीच बाद में हुए समझौते को देखते हुए, एम.जी.जी. और आर.यू आई.ए.एस. के बीच कोई विवाद नहीं है। इसलिए, एस. यू. आई. टी. एस.-II और II को बर्खास्त करने की आवश्यकता है क्योंकि जहां तक एम.जी.जी. और उसके अधिकारियों आदि की बात है, न तो एम.एच.एल. और न ही जी.जी.एल. आर.यू आई.ए.एस. को उन मुकदमों पर वाद हेतुक लिए मजबूर कर सकते हैं।

37. फिर हमारे पास अन्य प्रतिवादियों (जी. जी. 1 और एम.एच.एल. आदि) के खिलाफ एस. यू. आई. टी. एस. आई. जे. और II के जारी रहने के सवाल बचे हैं। और शेयरों की भौतिक अभिरक्षा के संबंध में प्रार्थनाएँ।जैसा कि पहले से ही 5.12.2002 दिनांकित समझौते से देखा गया है, एमजीजी और आरयूआईएएस 75001 शेयरों के ठिकाने और अभिरक्षा के बारे में अनिश्चित हैं!बी.ओ.सी.एल. जो शुरू में एम.जी.जी. द्वारा अधिग्रहित किया गया था। आर.यू आई.ए.एस. ने यह अच्छी तरह से जानते हुए कि एम.जी.जी. उपरोक्त 75001 शेयरों की अभिरक्षा नहीं देने जा रहा है, दिनांक 5.12.2002 परसमझौता किया, कथित रूप से उक्त शेयरों को खरीदने के लिए सहमत हुआ और एस. यू. आई. टी. एस.-II और [आई. के खिलाफ एम.जी.जी. पर मुकदमा नहीं चलाने के लिए सहमत हुआ। ऐसे मामले में, जी.जी.एल. या एम.एच.एल. या उसके एजेंटों

आदि के खिलाफ केवल शेयरों की अभिरक्षा के लिए मुकदमे जारी रखना, हमारी राय में, आर.यू आई.ए.एस. की ओर से बिना किसी वाद हेतुक है। इस संबंध में एस. यू. आई. टी.-II और III में प्रार्थनाएँ हैंः

(ii) कि चौथे प्रतिवादी संख्या 1,3,4 और 5 को आदेश दिया जाए और संबंधित वाद को देने/वापस करने का आदेश दिया जाए यदि उक्त 45-004 75,001 सभी संचय के साथ साझा करता है। 23 जून, 1997 ऐसी शर्तों पर जो यह माननीय न्यायालय निर्देश देता है।

सुइट-II

जे) कि प्रथम प्रतिवादी को आदेश दिया जाए और यह आदेश दिया जाए कि वह 23 जून 1997 से संबंधित वादी को उक्त 45,001 शेयरों को सभी परिवर्धनों के साथ ऐसी शर्तों पर वितरित/वापस करेगा जो यह माननीय न्यायालय निर्देश देता है।

एसयूआईटी-II

अर्थात आर.यू आई.ए.एस. के पक्ष में घोषणा के लिए कि वे एम.जी.जी., जी.जी.एल. और एम.एच.एल. ई. टी. ई. के विरुद्ध संयुक्त रूप से 75001 शेयरों की वसूली के हकदार हैं।आर.यू आई.ए.एस. एम.जी.जी. के खिलाफ मुकदमों पर मुकदमा नहीं चलाने के लिए सहमत होने के बाद उन मुकदमों में अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमों को जारी नहीं रख सकता है जिनका दावा (यदि कोई हो) एम.जी.जी. के अधिकार और अधिकार पर आधारित है।

इसलिए, हमारी राय में, एस. यू. आई. टी. एस.-II और आई. एल. की निरंतरता है, पूरी तरह से बिना किसी वाद हेतुक और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग। इसलिए उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए और तदनुसार बर्खास्त किया जाना चाहिए। नतीजतन, उक्त दो मुकदमों से उत्पन्न कार्यवाही में विभिन्न न्यायालयों (इस न्यायालय

सहित) द्वारा पहले पारित किए गए सभी अंतरिम आदेश समाप्त हो जाते हैं।हम यह भी घोषणा करते हैं कि एस. यू. आई. टी.-I से उत्पन्न होने वाली किसी भी कार्यवाही में किसी भी न्यायालय द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश भी जी.जी.एल. द्वारा मुकदमा को वापस लेने के मद्देनजर समाप्त हो गए।

इसलिए, एम.एच.एल. और जी.जी.एल. द्वारा दायर ये एस. एल. पी. कथित रूप से विभिन्न आवेदनों में पारित विवादित आदेशों से व्यथित हैं।आर.यू आई.ए.एस. द्वारा दायर दो मुकदमों में दायर किया गया मुकदमा निष्फल हो जाता है।इसलिए, उनसे उत्पन्न होने वाली उक्त एसएलपी को खारिज कर दिया जाता है।

38. परिणामी तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार होगीः

(i) समझौता-II के अनुसार आर.यू आई.ए.एस. से खरीदे गए बी.ओ.सी.एल. के 45001 शेयरों में एम.जी.जी. द्वारा अर्जित कानूनी अधिकार (जो भी वे हैं) आर.यू आई.ए.एस. को वापस कर दिए जाने चाहिए, जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि एम.जी.जी. द्वारा एम.एच.एल. के पक्ष में सहमति पुरस्कार दिनांक 21.09.2000 के अनुसार 45001 शेयरों के कथित हस्तांतरण ने एम.एच.एल. के पक्ष में कोई अधिकार या ब्याज पैदा किया है। एम.एच.एल. के इस तरह के दावे की जांच केवल एम.एच.एल. द्वारा दायर एस. यू. आई. टी.-IV में की जा सकती है।

(ii) आर.यू आई.ए.एस. के पक्ष में दिनांकित 05.12.2002 समझौते के आधार पर उन्हें हस्तांतरित आदेशने के लिए कथित एग्रीमेंट-II एम.जी.जी. के अनुसार एम.जी.जी. द्वारा जनता से 30000 अन्य शेयरों का अधिग्रहण किया गया था। यदि जी.जी.एल. या एम.एच.एल. में से किसी का उन शेयरों पर कोई दावा है, तो ऐसा दावा उनके द्वारा कानून के अनुसार किया जाना

चाहिए और स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन आर.यू आई.ए.एस. द्वारा दायर मुकदमों में नहीं। इस तरह के दावे को स्थापित आदेशने के लिए, एम.एच.एल. ने पहले ही एस. यू. आई. टी.-टी. वी. दायर आदेश दिया है, जिसमें गोयल और अन्य के अलावा जी.जी.एल. और एम.जी.जी. दोनों पक्ष हैं।

39. हालाँकि, एमजीजी के अलावा किसी अन्य पक्ष में उपर्युक्त शेयरों के लिए आज तक किसी भी कानूनी रूप से स्थापित स्वामित्व की अनुपस्थिति में में, क्या आरयूआईएएस दिनांकित समझौते के अनुसार उक्त शेयरों के धारकों के रूप में बीओसीएल के रजिस्टरों में अपने नाम दर्ज कराने का हकदार होगा, यह आरयूआईएएस के लिए पता लगाने का विषय है।तथापि, ऐसी पात्रता, यदि कोई हो, एस. यू. आई. टी.-IV के परिणाम के अधीन होनी चाहिए।

40. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम इस आदेश द्वारा बी.ओ.सी.एल. के 75001 शेयरों में एम.एच.एल. या जी. जी. ई. के पक्ष में किसी भी अधिकार या इसकी प्रवर्तनीयता का अस्तित्व या अन्यथा निर्णय नहीं ले रहे हैं। यह उनके लिए सूट-IV में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए खुला है। एस. यू. आई. टी.-IV में प्रतिवादियों को कानून में उपलब्ध हर बचाव और तथ्य को उठाने की स्वतंत्रता है।

41.आर.यू आई.ए.एस. और एम.जी.जी. दोनों ने अदालत को यह समझाने के लिए बहुत प्रयास किया कि पक्षों के बीच लंबी मुकदमेबाजी को देखते हुए इस अदालत को विभिन्न पक्षों के बीच इन शेयरों में अधिकारों, स्वामित्व और हित के सभी प्रश्नों की जांच करनी चाहिए जैसे कि यह इन विभिन्न मुकदमों की सुनवाई करने वाली पहली अदालत थी।

42. इन एसएलपी में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों की जांच, हमारी राय में, उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में पूरी तरह से अनावश्यक है।

43. सभी मुकदमों का शुद्ध प्रभाव यही है।पिछले 18 वर्षों से मुकदमा चल रहा है।इस मुकदमे पर इस देश का काफी न्यायिक समय व्यतीत होता है।इस मुकदमे के किसी भी पक्ष का आचरण अच्छा नहीं है।तत्काल एसएलपी विभिन्न अंतर्वर्ती कार्यवाहियों से उत्पन्न होती हैं।लगभग 18 कार्य दिवसों की अवधि के लिए दोनों पक्षों की ओर से तर्क दिए गए जैसे कि यह न्यायालय विभिन्न उपर्युक्त मुकदमों की सुनवाई करने वाला मूल क्षेत्राधिकार का न्यायालय हो।तथ्य यह है कि अभी तक किसी भी मुकदमे में मुद्दे भी नहीं बनाए गए हैं।पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बहुत जोरदार आग्रह किया कि मुकदमे की एक अंतिमता होनी चाहिए और इसलिए इस न्यायालय को भारी मुकदमेबाजी द्वारा उठाए गए तथ्य और कानून के हर सवाल की जांच करनी चाहिए, हमारा मानना है कि यह केवल पक्षकार हैं जिन्हें स्थिति के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए।यह मामला, हमारे विचार में, पैसे की शक्ति के साथ बेईमान वादियों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, यह सब कानूनी अधिकारों के नाम पर आधे-अधूरे सच, भ्रामक अभ्यावेदन और तथ्यों को दबाने का सहारा लेकर किया गया है।प्रत्येक पक्ष उपर्युक्त गलत आचरणों में से एक या दूसरे के लिए दोषी है।इसे प्रदर्शित किया जा सकता है (अधिक विस्तृत व्याख्या से लेकिन हमारा मानना है कि अब तक बताए गए तथ्य संकेत देने के लिए पर्याप्त होंगे) लेकिन हम इन मामलों में और समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं।

44. यह मामला एक मुकदमे के प्रत्येक अंतर्वर्ती कदम पर 'न्याय के मुकदमा लड़ाई' के नाम पर अमीर और शक्तिशाली लोगों द्वारा अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग के प्रमाण के रूप में भी काम करना चाहिए।इस मुकदमे पर इस न्यायालय और दो उच्च न्यायालयों का भारी न्यायिक समय खर्च किया गया था।इसका अधिकांश हिस्सा टालने योग्य है और अधिक योग्य मामलों पर अच्छी तरह से खर्च किया जा सकता था।

रामरामेश्वरी देवी और अन्य में यह न्यायालय।निर्मला देवी और अन्य, (2011) 8 एस. सी. सी. 249 पैरा 54 पर मनाया गया;

> "54. लागत लगाते समय हमें व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना होगा और यथार्थवादी होना होगा कि विभिन्न अदालतों के समक्ष मुकदमे को लड़ने में प्रतिवादी या प्रतिवादी को वास्तव में क्या करना पड़ा।हमें वकीलों की प्रचलित शुल्क संरचना और अन्य विविध खर्चों को भी व्यापक रूप से ध्यान में रखना होगा जो जवाबी-हलफनामे का मसौदा तैयार करने और दाखिल करने, टाइपिंग, फोटोकॉपी, अदालत शुल्क आदि के लिए विविध शुल्कों के लिए किए जाते हैं।"

45. इसलिए हम तीनों पक्षों यानी जी.जी.एल., एम.जी.जी. और आर.यू आई.ए.एस. में से प्रत्येक द्वारा भुगतान की जाने वाली Rs.25,00,000.00 (केवल पच्चीस लाख रुपये) पर अनुकरणीय लागत लागू करना उचित समझते हैं। उक्त राशि का भुगतान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को इस देश के न्यायिक समय के नुकसान के मुआवजे के रूप में किया जाना है और इसका उपयोग राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब वादियों को इस न्यायालय के समक्ष योग्य मामलों में अपने दावों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

देविका गुजराल एसएलपी का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।